जागो भारत

देश की दूसरी आज़ादी के लिए एक जनअभियान

'जागो भारत' एक अराजनीतिक जाति विहीन, दलविहीन, सामाजिक जनअभियान है। इस अभियान की शुरूआत 2008 में भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई तमाम अव्यवस्थाओं /अन्यायों के कारण पैदा हुई उस मानसिक वेदना से हुई जिस पर ड्राइंग रूम या चाय की दुकान पर खड़े होकर आम आदमी बहस तो करता है लेकिन इससे लड़ने के नाम पर यह कहकर खामोश बैठ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा मानना है कि सब कुछ हो सकता है जब हम जैसे लोग निराशा से निकलकर सक्रिय हो जायेंगे। अभियान में सभी सहभागी वालंटियर है।

आदिम समाज से आधुनिक सभ्यता तक का मनुष्य का विकास यथास्थिति से निरंतर टकराव का परिणाम है। गतिशील सभ्यताएं यथास्थिति से टकराकर ही आगे बढ़ती हैं। भारतीय लोकतंत्र आज जिस मुकाम पर है उसे भले ही हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहें, किन्तु बड़ा होने के साथ—साथ वह दुनिया का सबसे भ्रष्ट और जनता के लिए अकल्याणकारी लूटतंत्र है। लोकतंत्र में भले ही जनता को सर्वोपरि और शक्तिमान कहा गया हो, किन्तु भारतीय लोकतंत्र में इसका ठीक उल्टा है।

यह 'जागो भारत' अभियान इस उल्टे को सीधा करने की एक जरूरी और अनिवार्य पहल है। भले ही अभी यह पहल पत्थर में सर टकराने जैसी स्थिति का संकेत करती हो, किन्तु एक साथ जब जनसमूह के सर टकराएंगे तो यथास्थितिवाद का पत्थर भी टूटेगा और लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसकी आदर्श कल्पना भगत सिंह ने की थी साकार होगी। आजादी के 68 साल में हमारे शहीदों का सपना चकनाचूर हुआ है और आज से 68 साल पूर्व हासिल की गई आजादी एक तरह से ऐसी गुलामी में तब्दील हो गई है, जिसमें गुलाम बनाने वाले अब अंग्रेज नहीं बल्कि इसी देश के राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति, माफिया तथा आपराधिक राजनीति में लिप्त काले अंग्रेज हैं।

इस विकल्पहीन माहौल में 'जागो भारत' जन अभियान एक सार्थक विकल्प बनकर जनता के समक्ष आया है, जिसमें जनता ही इस लड़ाई को लड़ेगी जिसके जरिये वो अपने अधिकार और मनुष्य होने की गरिमा हासिल करेगी। ❑

लूट तंत्र को लोकतंत्र में बदलने के लिए 'जागो भारत' के प्राथमिक लक्ष्यः

- ☞ अंग्रेजों का कानून बदलकर अपना लोकहितकारी कानून बनाना
- ☞ देश के बच्चों/युवाओं में ऐसी जागृति पैदा करना कि वे भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हाथों में लेकर इसको धनबल, बाहुबल, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एवं परिवारवादी परम्परा वाले दलों/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की तरह चल रहे दलों से मुक्त करायें
- ☞ सरकारों को जनता के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, आवास की गारण्टी देने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में एकरूपता लाने के लिए बाध्य करना
- ☞ आय से अधिक सम्पत्ति को तत्काल जब्त कराकर तथा विदेशी बैंकों में जमा पूंजी को देश में वापस ला करके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। देश के हर नागरिक को उत्पादन या सेवा से अनिवार्य रूप से जोड़ना। उत्पादनपरक रोजगार वृहद स्तर पर सृजन कर देश की विशाल जनशक्ति का उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए करना जिससे ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके।
- ☞ दुनिया के उन देशों की तरह मतदान को अनिवार्य व स्वच्छ बनाना। सभी को अनिवार्य रूप से वोट देने के लिए प्रेरित करना
- ☞ जाति विहीन राजनीति की स्थापना एवं विस्तार करना
- ☞ अन्याय का प्रतिकार न करना कायरता है इसलिए अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित करना
- ☞ (सरकारी खजाने) जनता का पैसा से किसी भी जनप्रतिनिधि / जनसेवक पर एक नई पाई न खर्च हो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित करना क्योंकि जो नेता अपना शरीर अच्छी तरह नहीं चला पा रहे हैं वे देश चलाने का दम भरते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने स्वास्थ्य लाभ और ऐश आराम पर खर्च करते हैं
- ☞ परिवारवादी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की तरह चल रहे राजनीतिक दलों का अस्तित्व राजनीति से मिटाना
- ☞ 65 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति की कुशलता का उपयोग करना परन्तु इक्जीक्यूटिव पोस्ट पर बैठने से रोकना
- ☞ कृषि/कृषि आधारित उद्योगों पर बजट का 50 प्रतिशत खर्च करने के लिए सरकारों को बाध्य करना
- ☞ महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी समर्थ बनाकर (आरक्षण से नहीं) सुनिश्चित करना।
- ☞ जन प्रतिनिधियों, नौकरशाहों, न्यायतंत्र के लोगों और जनता को समाज/देश के प्रति जवाब देह बनाना। ❑

कौन जुड़ सकता है?

हर वह शख्श (बच्चा/युवा/वृद्ध) जो-

- ◆ हमारे विचार/लक्ष्य से सहमत हो
- ◆ भारतीयता में विश्वास करता हो
- ◆ भारतीय राजनीति को धनबल, बाहुबल, भ्रष्टाचार, कार्पोरेटराइजेशन, परिवारवादी परम्परा वाली पार्टियों एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की तरह चल रही पार्टियों से मुक्त करके इसे अच्छे इंसानों के हाथ में सौंपना चाहता हो
- ◆ मानता हो कि जब लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है तो आम जनता पर जो नियम/कानून लागू होते हैं वही सब पर लागू हों। जो कानून इसके बनाने, लागू करने व समीक्षा करने वालों पर न लागू हो वह जनता पर भी न लागू हो। किसी को विशेषाधिकार/विशेष सुविधायें न मिलें
- ◆ राजनीति को व्यवसाय न मानकर समाज सेवा ही माने
- ◆ राष्ट्रऋण उतारने के लिए राष्ट्रकाज में लगने को संकल्पित हों

यह अनवरत् चलने वाला अभियान है जो तब तक चलता रहेगा जब तक हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। ❑

मित्रों,

देश आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, विदेशी आतंकवादियों अलगाव वादियों से ज्यादा इन देशी लुटेरों से खतरा है। महंगाई, भुखमरी, अराजकता, अपराध, सरकारी खजाने (जन—धन) की लूट ने जनसामान्य का जीना दूभर कर दिया है। जिन पर देश को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी है वे रक्षक के वेश में भक्षक की भूमिका निभा रहे हैं।

जरा सोचिए - ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाले (सरकारी खजाने में जो भी धन है वह जनता का है) हमें गुलाम कैसे बनाये हुए हैं?

हम उनके मोहताज क्यों हैं? लोकसेवक, राजा/रानी/महाराजा क्यों बन गये? हम पर लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र कैसे थोप दिया गया? क्या आजादी इन चंद लुटेरों के लिए ली गयी थी? सन् 1947 में देश पर कोई कर्ज नहीं था आज हर देशवासी पर लगभग 45 हजार का कर्ज कैसे हो गया? ये पैसा गया कहाँ?

यदि आप जागरूक हैं तो हमारे साथ आइये हम इन लुटेरों को सबक सिखायेंगे इनसे आपको मुक्ति दिलायेंगे अन्यथा ये वर्तमान तो नष्ट कर ही चुके हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी अंधकारमय बना देंगे।

याद रखिये "जिन्दा (साहसी/वीर) ही अपनी रक्षा कर पाते हैं जो कायर हैं वे मुर्दा हैं।"

आज देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कानून से ज्यादा इच्छाशक्ति की जरूरत है। भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार करें।

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट
संस्थापक वालंटियर

एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर हजारों चने पैदा कर सकता है।

मुद्रकः जजमेंट आजतक, 5 पार्क रोड, लखनऊ कम्पोजिंग एवं पृष्ट सज्जा : एम.एफ. आजम 'फारूक' e-mail : judgementaajtak@gmail.com